



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2005/भाद्र 23, 1927

No. 389]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2005/BHADRA 23, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2005

सं. 82/2005-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 585(अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2841 61 के अंतर्गत आने वाले, चीन जनवादी गणराज्य, ताईपेई और हांगकांग (जिनको इसके पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए, पोटेशियम पैरमेगनेट (जिसे इसके पश्चात संबद्ध माल कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 10 सितम्बर, 2001 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि—

(क) संबद्ध देशों से पोटेशियम पैरमेगनेट का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ था ;

(ख) भारतीय उद्योग को तात्त्विक क्षति हुई थी;

(ग) घरेलू उद्योग को यह क्षति संबद्ध देशों से आयात के कारण हुई थी;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा०का०नि० 815 (अ), तारीख 1 नवम्बर, 2001 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1 नवम्बर, 2001 में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 113/2001-सीमाशुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 2001 द्वारा संबद्ध माल पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था । तत्पश्चात सीमाशुल्क, तदेन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधीकरण (सिगॉट) के आदेश सं० 3/2002 तारीख 28 अक्टूबर, 2002 के मद्देनजर उक्त अधिसूचना सं० 113/2001-सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 85/2003-सीमाशुल्क, तारीख 27 मई, 2003 (सा०का०नि० 436 (अ), तारीख 27 मई, 2003) द्वारा अतिक्रमण किया गया था;

और अभिहित प्राधिकारी अपने मध्यावधि समीक्षा अधिसूचना सं० 15/2/2004-डीजीएडी, तारीख 3 जून, 2005 में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि

(1) चीन गणराज्य से संबद्ध माल उनके उचित मूल्य से कम कीमत पर आयी है और चीन से आयात की गई संबद्ध माल के पाटन मार्जिन वास्तविक और न्यूनतम से अधिक हैं;

(2) यदि शुल्कों को समाप्त किया जाता है तो चीन से पाटन के जारी रहने या पुनः होने की भी संभावना है;

(3) इस समय घरेलू उद्योग को मामूली वास्तविक क्षति होना जारी है और मौजूदा क्षति मुख्यतः चीन आयात से हुए पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण है;

(4) यदि चीन गणराज्य से होने वाले आयातों पर से शुल्क हटा लिए जाते हैं तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना है;

(5) इसलिए पाटन को निष्प्रभावी बनाने के लिए चीन के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क जारी रखना आवश्यक है;

(6) क्षति जांच अवधि के दौरान कोई आयात नहीं हुए हैं इसलिए चीनी ताईपेई और हांगकांग से कोई पाटन नहीं हुआ है। इन दोनों देशों में संबद्ध माल का कोई उत्पादन भी नहीं हुआ है इसलिए यदि शुल्कों को समाप्त किया जाता है तो चीनी ताईपेई से पाटन के जारी रहने और/अथवा पुनः होने की कोई संभावना नहीं है। तथापि चीनी मूल की वस्तुओं के पुनः पुनः निर्यात अथवा यानांतरण, यदि कोई हो, को चीन के विरुद्ध लागू शुल्क के अंतर्गत समुचित रूप से कवर किया जायेगा इसलिए इन दोनों देशों के विरुद्ध शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता नहीं है।

और यह सिफारिश की है कि

“चीन जनवादी गणराज्य में उदगमित या वहां से निर्यातित संबद्ध माल के आयातों पर पाटन के मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखी जाये”

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ, पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण। नियम, 1995 के नियम 23 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित उक्त धारा 9क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 85/2003—सीमाशुल्क, तारीख 27 मई, 2003 (सा०का०नि० 436 (अ), तारीख 27 मई, 2003) का अतिक्रमण करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देशों में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है, दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं०	उपशीर्ष सं०	माल का विवरण	माल की विशिष्टता	उदगम देश	निर्यातक	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन इकाई	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	284161	पोटाशियम परमेगनेट केएमएन04	सभी श्रेणी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	मै० गुपस्टार युनान एलएलसी, चीन	कोई	285	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	284161	पोटाशियम परमेगनेट केएमएन04	सभी श्रेणी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई (उपरोक्त के सिवाय)	कोई	352	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	284161	पोटाशियम परमेगनेट केएमएन04	सभी श्रेणी	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	352	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क 11 मार्च, 2006 तक प्रभावी होगा और वह भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) की उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/7/2001-टी.आर.यू. (भाग-I)]

अजय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2005

No. 82/2005-CUSTOMS

G.S.R. 585(E).— Whereas, in the matter of import of Potassium Permanganate, falling under sub heading No. 2841 61 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from People's Republic of China, (hereinafter referred to as "P.R. of China") Chinese Taipei and Hong Kong, the designated authority, vide its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary I, Section 1, dated the 10th September, 2001 had come to the conclusion that—

- (a) Potassium Permanganate, originating in or exported from People's Republic of China, Chinese Taipei and Hong Kong, have been exported to India below normal value, resulting in dumping;
- (b) the Indian industry has suffered material injury;
- (c) the injury has been caused cumulatively by the dumped imports from the subject countries;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on Potassium Permanganate vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 113/2001 dated 1st November, 2001, [G.S.R. 815(E), dated the 1st November, 2001], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st November, 2001. Subsequently, in view of the erstwhile Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal's order No.03/2002-AD, dated the 28th October, 2002, Notification No.113/2001-Customs dated the 1st November, 2001, was superseded by Notification No. 85/2003-Customs dated the 27th May, 2003, [G.S.R. 436(E), dated the 27th May, 2003], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 27th May, 2003;

And whereas, the designated authority, vide its final findings in mid-term review notification No.15/2/2004-DGAD, dated the 3rd June, 2005, has come to the conclusion that—

- (1) The subject goods have entered from the People's Republic of China at less than its fair value and the dumping margins of the subject goods imported from the People's Republic of China are substantial and above de minimis level;
- (2) There is also a likelihood of dumping to continue or recur from the People's Republic of China if the duties are revoked;
- (3) The domestic industry continues to suffer marginal material injury at present and the cause of the current injury is due to the volume as well as price effect of the dumped imports from the Republic of China;
- (4) Injury to domestic industry is likely to continue if the duties are revoked in respect of imports from People's Republic of China;
- (5) Therefore, continued imposition of the antidumping duty is warranted against goods originating in or exported from the People's Republic of China to offset dumping;

- (6) There is no imports and therefore, dumping from Chinese Taipei, and Hong Kong, during the injury investigation period. There is also no production of the subject goods in these two countries. Therefore, there is no likelihood of dumping to continue and/or recur from Chinese Taipei, if the duties are revoked. However, re-export or transshipment of goods of Chinese origin, if any will be adequately covered under the duty imposed against the People's Republic of China. Therefore continued imposition of duty against these two countries is not warranted,

and recommended

“Continued imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from People's Republic of China, equal to lower of margin of dumping and the margin of injury, so as to offset dumping and remove the injury to the domestic industry”.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with sub-sections (5) and (6) of the said section 9A and rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.85/2003-Customs dated the 27th May, 2003 [G.S.R.436(E), dated the 27th May, 2003], except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading or tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4) of the said Table, originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), when exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table.

Table

Sl. No.	Sub. Heading	Description of goods	Specific ation of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit	Curre ncy
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	284161	Potassium Permanganate KmnO ₄	All grades	P.R.of China	Any	M/s Groupstar Yunnan, LLC, China	Any	285	MT	US \$
2	284161	Potassium Permanganate KmnO ₄	All grades	P.R.of China	Any	Any (other than above)	Any	352	MT	US \$
3	284161	Potassium Permanganate KmnO ₄	All grades	Any	P.R.of China	Any	Any	352	MT	US \$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective up to and inclusive of the 11th day of March, 2006, and shall be paid in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, -

(a) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 Of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/7/2001-TRU (Pt.-I)]

AJAY, Under Secy.

275048/25-2